

[2024] 7 एस.सी.आर. 287 : 2024 आईएनएससी 484

आबकारी आयुक्त कर्नाटक और अन्य

बनाम

मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2168 वर्ष 2007)

08 जुलाई 2024

[बी.वी. नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान,* न्यायाधीश]

विचारणीय मुद्दा

क्या आयकर अधिनियम की धारा 206सी के प्रावधान अपीलकर्ता के संबंध में लागू होते हैं और क्या वे शराब विक्रेता (ठेकेदार) जिन्होंने नीलामी में अपीलकर्ता से बिक्री अधिकार खरीदे हैं, आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के अर्थ में "खरीददार" माने जा सकते हैं या उक्त अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के खंड (iii) के अनुसार "खरीददार" की उक्त परिभाषा से बाहर रखे जा सकते हैं। उपरोक्त मूल मुद्दे से संबंधित प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उक्त आदेशों को दी गई चुनौती को खारिज करने में न्यायसंगत निर्णय लिया था।

शीर्ष टिप्पणियाँ

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 206सी की व्याख्या (क)(iii) - कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965 - कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक वेंड लाइसेंस की विशेष शर्तें) नियम, 1967 - नियम 4 - कर्नाटक उत्पाद शुल्क (शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969 - कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक का निर्माण और बोतलबंदी) नियम, 1987 - दिनांक 17.01.2001 के आदेश द्वारा, निर्धारण अधिकारी ने माना कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी के अनुसार अपीलकर्ता "विक्रेता" है और शराब विक्रेता "खरीदार" हैं, इसलिए अपीलकर्ता शराब विक्रेताओं (ठेकेदारों) से स्रोत पर आयकर वसूलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था- दिनांक 17.01.2001 के उक्त आदेश को चुनौती के पहले एकल न्यायाधीश और फिर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उचित हो या न हो खारिज कर दिया।

अभिनिर्धारित: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क)(iii) में किसी व्यक्ति को स्पष्टीकरण (क) में दी गई परिभाषा के अनुसार “खरीददार” के अर्थ से बाहर रखने के लिए दो शर्तें निर्धारित की गई हैं - पहली शर्त यह है कि माल उसे नीलामी के माध्यम से प्राप्त न किया गया हो - दूसरी शर्त यह है कि खरीददार द्वारा बेचे जाने वाले ऐसे माल का विक्रय मूल्य राज्य अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया हो - ये दोनों शर्तें शब्द से जुड़ी हैं- ‘और’ शब्द संयोजक है जिसका अर्थ है कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।

* लेखक

यह इन दोनों में से कोई भी नहीं है - इसलिए, स्पष्टीकरण (क) (iii) के अनुसार “खरीददार” की परिभाषा के दायरे से बाहर होने के लिए, दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है - इस मामले में, मैसूर सेल्स निर्दिष्ट क्षेत्र(क्षेत्रों) के लिए अराक के निर्माण और बोटलबंदी का लाइसेंसधारी है - नीलामी या निविदा या नीलामी-सह-निविदा आदि की प्रक्रिया द्वारा, उत्पाद शुल्क ठेकेदारों को चुना जाता है, जिन्हें बाद में अपने-अपने क्षेत्र(क्षेत्रों) में खुदरा अराक बेचने के लिए परमिट दिए जाते हैं - इन खुदरा विक्रेताओं, अर्थात् उत्पाद शुल्क ठेकेदारों को उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य का भुगतान करके मैसूर सेल्स द्वारा बनाए गए गोदाम या डिपो से अराक प्राप्त करना होता है - अराक सीलबंद बोटलों या सीलबंद पॉलीथीन पाउच में प्राप्त किया जाता है - इसलिए, दो अलग-अलग लेनदेन हैं - पहला लेनदेन खुदरा बिक्री के अधिकार के लिए नीलामी आदि की प्रक्रिया द्वारा उत्पाद शुल्क ठेकेदारों को चुनना है - दूसरा लेनदेन, जो पहले लेनदेन पर निर्भर है, परमिट प्राप्त करना है आबकारी ठेकेदारों द्वारा नीलामी के बाद सफल चयन हेतु जारी किए गए परमिटों के आधार पर खुदरा बिक्री के लिए अराक (एक प्रकार की शराब) का अधिकार - अतः यह स्पष्ट है कि आबकारी ठेकेदारों को नीलामी के माध्यम से अराक प्राप्त नहीं होती है - नीलामी के माध्यम से जो प्राप्त होता है वह नीलामी के आधार पर सफल चयन हेतु दिए गए परमिटों के आधार पर खुदरा बिक्री का अधिकार है - इस प्रकार, खंड (iii) के अंतर्गत पहली शर्त पूरी होती है - 1967 के नियमों का नियम 4 आबकारी ठेकेदार को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम तल मूल्य और अधिकतम सीमा मूल्य के दायरे में खुदरा में अराक बेचने की अनुमति देता है - खुदरा में बेची जाने वाली अराक का मूल्य बाजार की शक्तियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि एक पूर्व-निर्धारित सीमा के भीतर होता है - इसलिए, यद्यपि कानून द्वारा मूल्य सीमा निर्धारित की गई है, यह नहीं कहा जा सकता कि न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित होने के कारण विक्रय मूल्य निश्चित नहीं है - विक्रय मूल्य कानून द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन एक विशेष सीमा के भीतर, जिसके

बाहर, चाहे वह अधिक हो या कम, आबकारी ठेकेदार द्वारा खुदरा में अराक नहीं बेचा जा सकता - चूंकि स्पष्टीकरण (a) (iii) के अंतर्गत अनिवार्य दोनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए आबकारी ठेकेदार या अराक बेचने वाले शराब विक्रेता आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (a) के अंतर्गत परिभाषित "खरीददार" के दायरे में नहीं आएंगे - इस प्रकार, प्रश्न विचारणीय मुद्दे के रूप में प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है, यह मानते हुए कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी मैसूर बिक्री के संबंध में लागू नहीं होती है और जिन शराब विक्रेताओं (ठेकेदारों) ने अपीलकर्ता से नीलामी में बिक्री अधिकार खरीदे हैं, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के अर्थ में "खरीदार" नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं और परिणामस्वरूप, दिनांक 17.01.2001 के आदेशों को चुनौती देने वाली रिट अपील को खारिज करना उचित नहीं था। [पैरा 14.5, 15, 15.2, 16]

आयकर अधिनियम, 1961 - कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965 - कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक वेंड लाइसेंस की विशेष शर्तें) नियम, 1967 - कर्नाटक उत्पाद शुल्क (शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969 - कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक का निर्माण और बोतलबंदी) नियम, 1987 - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्व जिनका पालन किया जाना चाहिए:

अभिनिर्धारित: इस मामले में, यद्यपि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसका जवाब भी दाखिल किया गया था, फिर भी आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत पारित ऐसे आदेश के परिणामों को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं होगा। भले ही विधिक नोटिस और सुनवाई के संबंध में मौन हो, न्यायालय किसी भी पूर्वाग्रही आदेश को पारित करने से पहले नोटिस और सुनवाई की अंतर्निहित आवश्यकता को ध्यान में रखेगा। अतः, यह माना जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी के अंतर्गत आदेश पारित करने से पहले, निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व है कि वह संबंधित व्यक्ति को नोटिस दे और उसे व्यक्तिगत सुनवाई सहित पर्याप्त और उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करे। [पैरा 19]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

राव [1996] 2 एससीआर 570 : (1996) 3 एससीसी 465; ज्ञान चंद अशोक कुमार एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1991) 187 आईटीआर 188 (एचपी); के.के. मित्तल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1991) 187 आईटीआर 208 (पी एंड एच); स्टेट ऑफ बिहार बनाम कमिश्नर

ऑफ इनकम टैक्स (1993) 202 आईटीआर 535 (पीटीए); मेसर्स नरेश कुमार एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आईएलआर (2000) 2 पी एंड एच; सैनी एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2000) 246 आईटीआर 762 (एचपी); चंडीगढ़ डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2002) 253 आईटीआर 205 (पी एंड एच); भारत संघ बनाम ओम प्रकाश एस.एस. एंड कंपनी [2001] 1 एससीआर 1113 : (2001) 3 एससीसी 593 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961; कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965; कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक वेंड लाइसेंस की विशेष शर्तें) नियम, 1967; कर्नाटक उत्पाद शुल्क (शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969; कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक का निर्माण और बोतलबंदी) नियम, 1987।

प्रमुख शब्दों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क)(iii); आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के तहत परिभाषित क्रेता; शराब विक्रेता; नीलामी या निविदा या नीलामी-सह-निविदा की प्रक्रिया; खुदरा विक्रेता; उत्पाद शुल्क ठेकेदार; कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक बिक्री लाइसेंस की विशेष शर्तें) नियम, 1967 का नियम 4; प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत; सुनवाई का उचित अवसर।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2168 वर्ष 2007

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूर के दिनांक 13.03.2006 के निर्णय एवं आदेश से, अपील संख्या 7825, 7926 और 8021 वर्ष 2003

अधिवक्तागण

अविष्कार सिंहवी, सहायक अधिवक्ता, वी. एन. रघुपाथी, विवेक कुमार सिंह, नावेद अहमद,
भरत गर्ग, मनेंद्र पाल गुप्ता, अधिवक्ता

अपीलकर्ताओं के लिए।

बलबीर सिंह, सहायक अधिवक्ता, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज बहादुर यादव, श्रीमती अर्चना पाठक दवे, अनमोल चंदन, सुश्री निरंजना सिंह, प्रशांत सिंह द्वितीय, उदय खन्ना, इंद्रजीत प्रसाद, विजय नंद त्रिपाठी, दीपक कुमार, डॉ. नंद किशोर, राजेश महाले, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए.

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय: उज्ज्वल

भुयान, न्यायमूर्ति

पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (संक्षेप में "उच्च न्यायालय") की खंडपीठ द्वारा रिट अपील संख्या 7926/2003 में दिनांक 13.03.2006 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। उपरोक्त निर्णय और आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट अपील के साथ-साथ मैसूर सेल्स इंटरनेशनल, कर्नाटक राज्य और मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अन्य रिट अपीलों को खारिज कर दिया था, जिनमें उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.10.2003 को पारित सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 6869-6874/2001 और उपरोक्त पक्षों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "आयकर अधिनियम" कहा गया है) की धारा 206सी(6) के तहत दिनांक 17.01.2001 को पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अन्य रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997 और 1995-1996 के साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत जारी किए गए समान तिथि के परिणामी मांग नोटिसों के संबंध में, 17.01.2001 के आदेशों द्वारा निर्धारण अधिकारी ने माना कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी के अनुसार अपीलकर्ता "विक्रेता" हैं और शराब विक्रेता "खरीदार" हैं, इसलिए अपीलकर्ता उक्त निर्धारण वर्षों से संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए शराब विक्रेताओं (ठेकेदारों) से स्रोत पर आयकर वसूलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने कुछ राशियों को स्रोत पर आयकर के रूप में घोषित किया, जिसे अपीलकर्ता करने में विफल रहा। इसलिए, अपीलकर्ता को स्रोत पर आयकर कटौती के रूप में निर्धारित राशियों को जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, उपरोक्त राशियों पर ब्याज भी लगाया गया। इसके बाद मांग नोटिस जारी किए गए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17.01.2001 के उक्त आदेशों को दी गई

चुनौती को पहले विद्वान एकल न्यायाधीश और फिर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था।

3. इस अपील में विचारणीय मुख्य बिंदु यह है कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 206सी के प्रावधान अपीलकर्ता पर लागू होते हैं और क्या नीलामी में अपीलकर्ता से बिक्री अधिकार खरीदने वाले शराब विक्रेताओं (ठेकेदारों) को आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के अर्थ में "खरीददार" माना जा सकता है या उक्त अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के खंड (iii) के अनुसार "खरीददार" की उक्त परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है। उपरोक्त मुख्य मुद्दे से संबंधित प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उक्त आदेशों को दी गई चुनौती को अस्वीकार करने में न्यायसंगत निर्णय लिया था।

4. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने से पहले, मामले के प्रासंगिक तथ्यों का संक्षेप में वर्णन करना उचित होगा। मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे आगे "मैसूर सेल्स" भी कहा गया है) कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम है, जो अन्य बातों के अलावा, अराक के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। मैसूर सेल्स आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक करदाता है। अपीलकर्ता ने जुलाई 1993 में कर्नाटक राज्य के उत्पाद शुल्क कानूनों के तहत अराक के व्यापार में प्रवेश किया था। 1993 से पहले, कर्नाटक राज्य में कई निजी बॉटलिंग इकाइयाँ थीं जो अराक का निर्माण और बिक्री करती थीं। अराक की खुदरा बिक्री के लिए पट्टे का अधिकार प्रदान करने हेतु समय-समय पर नीलामी आयोजित की जाती थी। यह नीलामी निर्दिष्ट क्षेत्रों के संदर्भ में आयोजित की जाती थी। सफल बोलीदाताओं को बॉटलिंग इकाइयों से अराक प्राप्त करने और फिर उसे अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में खुदरा व्यापार में बेचने का अधिकार था। अराक व्यापार राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है।

4.1. कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965 (जिसे संक्षेप में "उत्पाद शुल्क अधिनियम" कहा गया है) कर्नाटक राज्य में एक समान उत्पाद शुल्क कानून प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उत्पाद शुल्क अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य में शराब और मादक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, खरीद और बिक्री तथा उन पर उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में तथा इससे संबंधित कुछ मामलों के लिए एक समान कानून बनाना आवश्यक है। उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत, उत्पाद शुल्क कानून के उचित प्रवर्तन के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक वेंड लाइसेंस की विशेष शर्तें) नियम, 1967 (इसके बाद "1967 नियम" कहा जाएगा);

(ii) कर्नाटक उत्पाद शुल्क (शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969 (इसके बाद संक्षेप में "1969 नियम" कहा जाएगा);

(iii) कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अराक का निर्माण और बोटलबंदी) नियम, 1987 (इसके बाद "1987 नियम" कहा जाएगा)।

4.2 वर्ष 1993 में, राज्य सरकार ने निजी बॉटलिंग इकाइयों को अराक के निर्माण या बॉटलिंग में संलग्न होने से रोक दिया और इसके बजाय एक नीति के रूप में इन कार्यों को राज्य सरकार की कंपनियों या उपक्रमों, जैसे कि मैसूर सेल्स और मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 2169/2007 में अपीलकर्ता, जिसे इस न्यायालय द्वारा 12.10.2023 को गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था) के हाथों में सीमित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, मैसूर सेल्स और मैसूर शुगर को राज्य सरकार की ओर से अराक की बॉटलिंग और विपणन का कार्य सौंपा गया। कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों के लिए यह कार्य मैसूर सेल्स को सौंपा गया था, जबकि राज्य के शेष भाग के लिए यह जिम्मेदारी मैसूर शुगर को सौंपी गई थी। अपीलकर्ता का कहना है कि सौंपा गया कार्य, अर्थात् राज्य की ओर से अराक की बॉटलिंग और विपणन, कार्य अनुबंध की प्रकृति का था।

4.3. एक बार अराक का निर्माण और बोटलबंदी हो जाने के बाद, यह कर्नाटक राज्य की संपत्ति बन जाती है, क्योंकि इसका स्वामित्व राज्य के पास होता है। आबकारी आयुक्त, अपीलकर्ता द्वारा किए गए खर्च को ध्यान में रखते हुए, आबकारी (शराब) विक्रेताओं या ठेकेदारों से अपीलकर्ता द्वारा वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण करता है। आबकारी ठेकेदारों को राज्य सरकार के खजाने में आवश्यक आबकारी शुल्क जमा करना होता है और फिर परमिट प्राप्त करना होता है, जिसके प्रस्तुत होने पर अपीलकर्ता उन्हें अराक की आपूर्ति करता है।

कर्नाटक राज्य, आबकारी अधिनियम के अनुसार करदाता द्वारा वसूल की जाने वाली राशि सहित संपूर्ण संचालन को नियंत्रित करता है।

4.4. सफल आबकारी ठेकेदार, उन्हें आवंटित क्षेत्रों के आधार पर मैसूर सेल्स और मैसूर शुगर से अराक प्राप्त करते हैं। शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार के पट्टे में एक निर्दिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में ऐसे अधिकार की नीलामी का प्रावधान है। खुदरा विक्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा 1967 के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मार्जिन विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

4.5. आयकर अधिनियम में धारा 206सी को वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 01.06.1988 से प्रभावी किया गया था। यह मादक पेय आदि के "विक्रेता" पर "खरीदार" द्वारा भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने का दायित्व डालता है। स्पष्टीकरण (क) के अनुसार, कुछ व्यक्तियों को "खरीदार" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इससे बाहर रखा गया है।

4.6. कर्नाटक के उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा 16.06.1998 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें एक परिशिष्ट भी जारी किया गया। परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि चूंकि अराक की प्राप्ति नीलामी के माध्यम से नहीं होती और अराक का विक्रय मूल्य उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए उत्पाद शुल्क (शराब) विक्रेताओं या ठेकेदारों से टीडीएस की वसूली का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

4.7. उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलकर्ता ने शराब विक्रेताओं से कोई टीडीएस नहीं काटा।

4.8. निर्धारण अधिकारी ने 26.10.2000 को नोटिस जारी कर करदाता से कारण बताने को कहा कि वह उन वित्तीय वर्षों के लिए, जो विचाराधीन निर्धारण वर्षों से संबंधित हैं, "खरीदारों" यानी उत्पाद शुल्क ठेकेदारों से अपेक्षित टीडीएस राशि क्यों न वसूल करे। ऐसा प्रतीत होता है कि करदाता ने इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत कर दिया था। इसके बाद, निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 17.01.2001 को आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत विचाराधीन निर्धारण वर्षों के लिए आदेश पारित किए। जैसा कि पहले बताया गया है, उपरोक्त आदेशों द्वारा करदाता को कुछ राशि टीडीएस के रूप में अदा करने का निर्देश दिया गया था, जिसे वह शराब विक्रेताओं या ठेकेदारों से वसूल करने में विफल रहा था। इन आदेशों के बाद, निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए करदाता को परिणामी मांग नोटिस भी जारी किए गए।

4.9. मैसूर सेल्स ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं। उनका मुख्य तर्क यह था कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) उन पर लागू नहीं होती, साथ ही एक संबंधित मुद्दा यह भी उठाया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 27.10.2023 के निर्णय और आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत पारित आदेशों की पुष्टि करते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

4.10. इसके बाद, मैसूर सेल्स और अन्य ने डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपीलें दायर कीं। हालांकि, 13.03.2006 के निर्णय और आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करते हुए रिट अपीलों को खारिज कर दिया गया।

5. उपरोक्त से असंतुष्ट होकर एसएलपी (सी) संख्या 12524/2006 दायर की गई। 23.04.2007 को अनुमति मिलने के बाद, इसे सिविल अपील संख्या 2168/2007 के रूप में पंजीकृत किया गया।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी श्री आविष्कार सिंहवी ने प्रस्तुत किया कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी मैसूर सेल्स पर लागू नहीं होती है, जो कर्नाटक सरकार द्वारा नियंत्रित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वास्तव में, यह एक सरकारी कंपनी है। यह अराक के निर्माण में लगी हुई है। अराक की बॉटलिंग आबकारी आयुक्त की देखरेख में की जाती है। जो भी अराक निर्मित होता है, वह केवल राज्य सरकार की संपत्ति है।

उत्पाद शुल्क खरीदार, अर्थात् शराब ठेकेदार, नीलामी में कोई अराक प्राप्त नहीं करते हैं। उन्हें केवल अराक की खुदरा बिक्री करने का अधिकार/लाइसेंस प्राप्त होता है। इसलिए, ऐसे ठेकेदार आयकर अधिनियम की धारा 206सी के तहत स्पष्टीकरण में परिभाषित "खरीदार" नहीं हैं।

6.1. माननीय एएजी ने तर्क दिया कि नीलामी में अराक का खुदरा या बिक्री अधिकार बेचा जाता है, न कि स्वयं अराक की नीलामी। अराक की अंतिम बिक्री ठेकेदारों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य पर की जाती है। इसलिए, उनका कहना है कि धारा 206सी मैसूर सेल्स जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर लागू नहीं होती है। स्पष्टीकरण (क)(ii) और (iii) दोनों स्पष्ट रूप से खुदरा विक्रेताओं को स्पष्टीकरण के तहत परिभाषित "खरीदारों" के दायरे से बाहर रखते हैं।

6.2. आगे विस्तार से बताते हुए, उन्होंने कहा कि उपर्युक्त अपवाद में आने वाले "खरीदारों" को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में अराक की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करते समय स्रोत पर आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई थी। नीलामी केवल राज्य में निहित अधिकार या विशेषाधिकार को शराब ठेकेदारों को हस्तांतरित करने से संबंधित है, जो इसके बाद अराक की खुदरा बिक्री का व्यवसाय संचालित करेंगे। इसलिए, नीलामी लेनदेन में कोई बिक्री शामिल नहीं है।

6.3. निर्धारण अधिकारी ने संघ ऑफ इंडिया बनाम ए. संन्यासी राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर गलत तरीके से भरोसा किया था। उक्त निर्णय में, आयकर अधिनियम की धारा 206सी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय द्वारा इसे नकार दिया गया था। हालांकि, निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि धारा 206सी में केवल अपवाद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें आयकर स्रोत पर वसूलने की आवश्यकता नहीं है।

6.4. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि आयकर अधिनियम में धारा 206सी को शामिल करने का उद्देश्य मादक पेय पदार्थों के व्यापार आदि से होने वाले लाभ और आय से संबंधित मामलों में उचित कर संग्रह सुनिश्चित करना था। हालांकि, कर कानून की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए। इसकी व्याख्या अत्यधिक व्यापक और विस्तृत तरीके से नहीं की जा सकती, जिससे

उन व्यक्तियों को कर के दायरे में लाया जा सके जो अन्यथा कर भुगतान से छूट प्राप्त हैं। एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने ऐसी व्याख्या अपनाने में गलती की और गलत तरीके से यह माना कि धारा 206सी मैसूर सेल्स के संबंध में लागू होती है और चूंकि इसने टीडीएस नहीं काटा था, इसलिए इसे वसूल किया जाना आवश्यक था। दोनों पीठों ने यह राय लेने में गलती की कि अराक की खरीद केवल सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से होती है, किसी अन्य तरीके से नहीं, और "विक्रेता" (मैसूर सेल्स) का दायित्व है कि वह ऐसे "खरीदारों" से स्रोत पर आयकर एकत्र करे जो आगे खुदरा बिक्री करेंगे।

6.5. राजस्व विभाग द्वारा लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए दृष्टिकोण को स्वीकार कर भी लिया जाए, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैसूर सेल्स द्वारा लाइसेंस धारकों को अराक की बिक्री हुई थी। ऐसी बिक्री, यदि ऐसा कहा भी जा सकता है, तो वह आबकारी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर हुई थी। यह बिक्री पूरी तरह से खुदरा बिक्री के उद्देश्य से थी और आयकर

अधिनियम की धारा 206सी के अर्थ में बिक्री नहीं थी; इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधान के तहत, बिक्री आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण में परिभाषित "खरीदार" को ही की जानी चाहिए। वास्तव में, अपीलकर्ता का तर्क है कि मैसूर सेल्स और आबकारी ठेकेदारों के बीच कोई बिक्री नहीं हुई है।

6.6. राजस्व विभाग ने यह गलत धारणा बनाई है कि सफल शराब ठेकेदारों द्वारा अराक की नीलामी और खरीद का कार्य आपस में अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और एक सामूहिक कार्रवाई का हिस्सा है। नीलामी में, सफल आबकारी ठेकेदारों को उनके आवंटित क्षेत्रों में अराक की खुदरा बिक्री के लिए परमिट/लाइसेंस दिए जाते हैं। इसके बाद, आबकारी ठेकेदार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के बीच अराक की बिक्री करते हैं। इसलिए, ऐसे लेन-देन को नीलामी के माध्यम से बिक्री या खरीद नहीं कहा जा सकता।

6.7. विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम की धारा 206 सी (6) के तहत आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया था। यह अधिकार क्षेत्र सहायक आयकर आयुक्त (टीडीएस)-1, बेंगलुरु को दिया गया था। अधिकार क्षेत्र के संबंध में अपीलकर्ता के इस तर्क को विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल तकनीकी तर्क मानते हुए खारिज कर दिया।

6.8. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 206 सी (6) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2001 को पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थे। करदाता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। बिना सुनवाई के ही उपरोक्त आदेश पारित किए गए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण ऐसे आदेश प्रारंभ से ही शून्य हैं। इस पहलू को उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने ही अनदेखा किया।

6.9. अतः उन्होंने निवेदन किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों के आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं। विचाराधीन निर्धारण वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2001 को पारित आदेश भी निरस्त और रद्द किए जाने योग्य हैं। तदनुसार दीवानी अपील स्वीकार की जाए।

6.10. अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:

- (i) ज्ञान चंद अशोक कुमार एंड कंपनी बनाम भारत संघ;
- (ii) के.के. मित्तल बनाम भारत संघ;
- (iii) बिहार राज्य बनाम आयकर आयुक्त;
- (iv) मेसर्स नरेश कुमार एंड कंपनी बनाम भारत संघ;
- (v) सैनी एंड कंपनी बनाम भारत संघ;
- (vi) चंडीगढ़ डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ; (vii) भारत संघ बनाम ओम प्रकाश एस.एस. एंड कंपनी।

7. राजस्व के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रारंभ में ही निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विवादित आदेश में ऐसी कोई त्रुटि या खामी नहीं है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। दीवानी अपील भ्रामक है और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है।

7.1. वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्धारण अधिकारी ने करदाता को नोटिस जारी किए थे और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन भी किया था। इसके बाद, निर्धारण अधिकारी ने माना कि शराब का विक्रय मूल्य निश्चित नहीं था। केवल न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य की सीमा ही निश्चित थी। कर्नाटक राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा वर्ष 2000 के लिए जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य क्रमशः 55 रुपये और 85 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया गया था। इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि शराब को एक विशिष्ट निश्चित मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठेकेदार न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच किसी भी दर पर शराब बेचने के लिए स्वतंत्र थे। शराब की बिक्री को प्रभावित करने वाली एक विस्तृत सीमा को देखते हुए, निर्धारण अधिकारी का यह मानना सही है कि शराब का विक्रय मूल्य निश्चित नहीं था।

7.2. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि निर्धारण अधिकारी का यह मत सही था कि उत्पाद शुल्क विक्रेताओं ने नीलामी के माध्यम से माल प्राप्त किया था, क्योंकि माल (अराक) केवल परमिट प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किया गया था, जो नीलामी में सफल बोली लगाने पर उपलब्ध थे।

7.3. इस प्रकार, शराब ठेकेदार आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के अंतर्गत "खरीददार" के अर्थ के दायरे में स्पष्ट रूप से आते हैं। इसलिए, मैसूर सेल्स पर शराब ठेकेदारों से स्रोत पर आयकर (टीडीएस) काटने का दायित्व था। ऐसा करने में विफल रहने के कारण, निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत दिनांक 17.01.2001 के आदेश पारित करना पूर्णतः उचित था।

7.4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी मुद्दों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया और दिनांक 17.01.2001 के आदेशों की पुष्टि की। इसी प्रकार, डिवीजन बेंच ने भी सभी मुद्दों की गहन जांच की और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2001 के आदेश पारित करना पूर्णतः उचित था। ऐसी स्थिति में, इस स्तर पर उच्च न्यायालय की एकल और डिवीजन बेंचों द्वारा पुष्टि किए गए निर्धारण अधिकारी के समवर्ती निष्कर्षों को बदलने का कोई कारण नहीं है। अतः, दीवानी अपील खारिज कर दी जानी चाहिए।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर न्यायालय ने विधिवत विचार किया है।

9. आयकर अधिनियम की धारा 206सी पर आगे बढ़ने से पहले, वर्तमान मामले के संदर्भ में कर्नाटक राज्य में लागू उत्पाद शुल्क कानून ढांचे का एक संक्षिप्त अवलोकन आवश्यक है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मूल अधिनियम उत्पाद शुल्क अधिनियम है, जो कर्नाटक राज्य में एक समान उत्पाद शुल्क कानून प्रदान करने वाला अधिनियम है। यह अधिनियम शराब और मादक पदार्थों के उत्पादन से लेकर बिक्री और उन पर उत्पाद शुल्क लगाने तक के संपूर्ण दायरे को कवर करता है। धारा 2 उत्पाद शुल्क अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है। धारा 2 (2) में "बोतल में भरना" शब्द का अर्थ शराब को पीपे या अन्य पात्र से बोतल, जार, फ्लास्क, पॉलीथीन पाउच या इसी तरह के किसी पात्र में बिक्री के उद्देश्य से स्थानांतरित करना बताया गया है, चाहे निर्माण की कोई प्रक्रिया अपनाई गई हो या नहीं, और इसमें पुनः बोतल भरना भी शामिल है। धारा 2 (19) में "निर्माण" को परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा कोई किण्वित, मादक या मादक पेय पदार्थ उत्पादित या तैयार किया जाता है, और साथ ही पुनर्आसवन तथा शराब के शुद्धिकरण की प्रत्येक प्रक्रिया भी शामिल है। धारा 3 (1) के अनुसार, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, कर्नाटक राज्य में उप आयुक्त से कम रैंक के अधिकारी को उत्पाद शुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है। वह उत्पाद शुल्क

अधिनियम के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी होगा। आबकारी आयुक्त की शक्तियों का वर्णन धारा 3 की उपधारा (2) में किया गया है। आबकारी विभाग के प्रशासन पर उनका समग्र नियंत्रण होगा।

9.1. धारा 17 विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा देने की शक्ति से संबंधित है। इसकी उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ऐसी शर्तों और ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, अनन्य या अन्य अधिकार निम्नलिखित को पट्टा दे सकती है:

(क) थोक विनिर्माण या बिक्री या दोनों का; या

(ख) थोक या खुदरा बिक्री का; या

(ग) थोक विनिर्माण या आपूर्ति या दोनों का तथा खुदरा बिक्री का

9.2. यद्यपि उपधारा (1क) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के अंतर्गत दिया गया कोई भी पट्टा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, फिर भी इसके परंतुक में राज्य सरकार को पट्टेदार को पट्टा या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित करने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। उपधारा (2) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी उपधारा (1) के अंतर्गत पट्टेदार को या उपधारा (1ए) के अंतर्गत हस्तांतरिती को उसके पट्टे की शर्तों के अनुसार लाइसेंस प्रदान कर सकता है। उपधारा (3) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के कारण पट्टे की समाप्ति का प्रावधान है। उपधारा (4) के अंतर्गत, जब उपधारा (3) के अनुसार पट्टा समाप्त हो जाता है, तो राज्य सरकार उपायुक्त को निर्देश दे सकती है कि वह अपने प्रबंधन के अंतर्गत अधिकार को अपने हाथ में ले ले और उसे पुनर्विक्रय या किसी अन्य माध्यम से पुनः पट्टे पर दे दे।

9.3. धारा 71 राज्य सरकार को उत्पाद शुल्क अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

10. कर्नाटक उत्पाद शुल्क (अरक बिक्री लाइसेंस की विशेष शर्तें) नियम, 1967 (जिसे ऊपर "1967 नियम" कहा गया है) कर्नाटक सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। 1967 नियमों का नियम 2 लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित क्षमता वाली अरक आदि की बिक्री से संबंधित है। नियम 2(1) कहता है कि खुदरा बिक्री द्वारा अरक बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक लाइसेंसधारी केवल निर्धारित

क्षमता वाली अरक ही बेचेगा। उप-नियम (2) के अनुसार, गोदाम या डिपो से प्राप्त सीलबंद बोतलों या सीलबंद पॉलीथीन पाउच में रखी गई अरक के अलावा कोई भी अरक लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के लिए नहीं रखी जाएगी या बेची नहीं जाएगी। नियम 3 काउंटर के निर्माण का प्रावधान करता है। नियम 3 के अनुसार, अराक बेचने का लाइसेंसधारी दुकान में एक मीटर से अधिक ऊंचा काउंटर नहीं बनाएगा। नियम 4 खुदरा मूल्य से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि उपायुक्त या आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के अधीन रहते हुए, लाइसेंसधारी अपनी इच्छानुसार दरों पर अराक बेच सकता है। नियम 5 का शीर्षक है, लाइसेंसधारी केवल गोदाम आदि से ही अराक खरीदेगा। उप-नियम (1) के अनुसार, खुदरा अराक बेचने का लाइसेंसधारी बिक्री के लिए आवश्यक मात्रा में अराक केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत गोदाम या डिपो से ही खरीदेगा, और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्य का भुगतान करेगा। यह प्रावधान प्रासंगिक होने के कारण, नीचे उद्धृत किया गया है:

5. लाइसेंसधारी द्वारा अरक की खरीद केवल गोदाम आदि से: -

(1) खुदरा अरक बेचने वाले लाइसेंसधारी को बिक्री के लिए आवश्यक मात्रा में अरक केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत गोदाम या डिपो से ही खरीदनी होगी, और इसके लिए आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्य का भुगतान करना होगा।

10.1. नियम 5(2) में स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंस प्राप्त परिसर में केवल अनुमोदित आकार की सीलबंद बोतलों में, जिन पर आबकारी लेबल लगे हों, या अधिकृत गोदाम या डिपो से प्राप्त सीलबंद पॉलीथीन पाउच में ही अरक बेची जाएगी।

10.2. नियम 6 में कहा गया है कि अरक की खेप सीलबंद होनी चाहिए। गोदाम या डिपो से जारी की गई अरक की सभी खेपों को गोदाम या डिपो के प्रभारी अधिकारी द्वारा इस प्रकार सीलबंद किया जाएगा कि सील के अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दें। परिवहन के दौरान सील टूटने की स्थिति में लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार परिवहन की गई शराब को लाइसेंसधारी द्वारा अपने खर्च पर, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित और गोदाम के प्रभारी अधिकारी की देखरेख में, बिक्री के उद्देश्य से ऐसे कंटेनरों में पैक किया जा सकता है।

11. कर्नाटक सरकार ने आबकारी अधिनियम की धारा 71 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक आबकारी (शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969 (जिसे

ऊपर "1969 नियम" कहा गया है) भी बनाए हैं। नियम 2(ग) के अनुसार, "शराब की खुदरा बिक्री का अधिकार" अभिव्यक्ति का अर्थ शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा है। नियम 3 खुदरा बिक्री के पट्टे से संबंधित है। नियम 3(1) के अनुसार, शराब की खुदरा बिक्री का अधिकार निविदा, नीलामी, निविदा-सह-नीलामी या राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से दिया जा सकता है। नियम 3(3) में प्रावधान है कि अराक की खुदरा बिक्री का अधिकार अनन्य अधिकार होगा, लेकिन केवल उन जिलों में जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, और उपभोक्ताओं को केवल बोटलबंद अराक या पॉलीथीन पाउच में अराक ही बेची जाएगी। नियम 3क सरकारी कंपनियों आदि को पट्टा देने से संबंधित है। उप-नियम (1) के अनुसार, 1969 के नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि सरकारी राजस्व के हित में या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य कारण से उचित समझे, तो राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी कंपनी या एजेंसी या राज्य सरकार के किसी विभाग को शराब की खुदरा बिक्री का पट्टा ऐसे नियमों और शर्तों पर दे सकती है जैसा वह उचित समझे।

11.1. आबकारी ठेकेदारों के पंजीकरण का प्रावधान नियम 4क में है। उप-नियम (1) के अनुसार, आबकारी ठेकेदार के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन आबकारी आयुक्त को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उप-नियम (2) से (4) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आबकारी आयुक्त उप-नियम (5) के तहत ऐसे आवेदक को आबकारी ठेकेदार के रूप में पंजीकृत कर सकता है और निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है जो हस्तांतरणीय नहीं होगा। उप-नियम (8) यह स्पष्ट करता है कि इस प्रकार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र, उस प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क वर्ष के लिए शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार के निपटान हेतु निविदा/नीलामी में भाग लेने के लिए वैध होगा।

11.2. नियम 10(1) के अनुसार, यदि किसी जिले के भीतर शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का निपटान नीलामी द्वारा किया जाना है, तो उस जिले का उपायुक्त और यदि किसी मंडल में एक से अधिक जिलों में अधिकार का निपटान करना है, तो उस मंडल का मंडल आयुक्त अधिसूचित तिथि, समय और स्थान पर नीलामी आयोजित करेगा। नीलामी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियम 11 में निर्धारित है।

12. आबकारी अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत, कर्नाटक सरकार ने नियमों का एक और समूह बनाया है जिसे कर्नाटक आबकारी (अराक का निर्माण एवं बोटलबंदी) नियम, 1987 कहा

जाता है (जिसे ऊपर “1987 के नियम” के रूप में संदर्भित किया गया है)। नियम 2(ख) में “अराक” को स्पिरिट को मिलाकर या कम करके निर्मित स्पिरिट के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें मसालेदार अराक शामिल हैं, लेकिन इसमें भारतीय या विदेशी शराब शामिल नहीं है। नियम 2(ग) में “मिश्रण” को समान या भिन्न सामर्थ्य वाली अन्य स्पिरिट के साथ स्पिरिट को मिलाने के रूप में परिभाषित किया गया है। नियम 2(ड) के अनुसार, “आयुक्त” का अर्थ आबकारी आयुक्त है। नियम 2(एन) में “गोदाम” को किसी भी आसवन या अन्य स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ अराक बनाने के लिए स्पिरिट का भंडारण, मिश्रण, परिपक्वता, सुदृढीकरण, तनुकरण या स्वादवर्धन किया जाता है, और साथ ही ऐसे अराक की बोतलबंदी का स्थान भी शामिल है, लेकिन इसमें शराब या भारतीय मादक पेय, बीयर या ताड़ी के निर्माण का कारखाना शामिल नहीं है।

12.1. नियम 3(1) के अनुसार, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अराक के निर्माण और बोतलबंदी के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है। नियम 3 का उप-नियम (2) बाद में 01.07.1993 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया। नियम 3 का उप-नियम (2) स्पष्ट करता है कि नियम 3 के अंतर्गत लाइसेंस केवल राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी या एजेंसी या राज्य सरकार के विभाग को ही जारी किया जाएगा। यह प्रावधान महत्वपूर्ण होने के कारण, नीचे उद्धृत किया गया है:

3. लाइसेंस केवल किसी कंपनी आदि को ही दिया जाएगा: -

(1) अराक के निर्माण और बोतलबंदी के लिए किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जब भी आवश्यक हो, आयुक्त द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

(2) इस नियम के अंतर्गत लाइसेंस केवल राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी या एजेंसी या राज्य सरकार के विभाग को ही जारी किया जाएगा।

12.2. नियम 8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई गोदाम एक से अधिक जिलों को सेवा प्रदान करता है, तो उस गोदाम को बोतलबंद अराक के भंडारण और खुदरा अराक बेचने का लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को अराक की आपूर्ति के लिए डिपो माना जाएगा। नियम 9 के तहत, आयुक्त गोदामों की संख्या, प्रत्येक गोदाम द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र और उनके स्थान का निर्धारण कर सकता है। नियम 16 में गोदाम से अराक हटाने का प्रावधान है। उप-नियम (1) के अनुसार, उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना गोदाम से अराक नहीं हटाया

जाएगा। उप-नियम (2) में कहा गया है कि अनुमोदित क्षमता और डिजाइन की बोतलों या पॉलीथीन पाउच के अलावा किसी अन्य रूप में गोदाम या डिपो से अराक जारी नहीं किया जाएगा। उप-नियम (3) के अनुसार, खुदरा अराक बेचने का लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को ही गोदाम या डिपो से अराक जारी किया जाएगा। नियम 17 में कहा गया है कि डिस्टिलरी द्वारा गोदाम को आपूर्ति की गई शुद्ध स्पिरिट के लिए सरकार द्वारा डिस्टिलरी को भुगतान की जाने वाली कीमत, अराक के निर्माण और बोतलबंदी के लिए सरकार द्वारा गोदाम को भुगतान की जाने वाली कीमत और अराक की खुदरा बिक्री के अधिकार के लिए पट्टेदारों द्वारा सरकार को बोतलबंद अराक की आपूर्ति के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित की जाएगी। नियम 17 प्रासंगिक होने के कारण, नीचे उद्धृत किया गया है:

17. कीमत निर्धारण: -

डिस्टिलरी द्वारा गोदाम को आपूर्ति की गई शुद्ध स्पिरिट के लिए सरकार द्वारा डिस्टिलरी को भुगतान की जाने वाली कीमत, अराक के निर्माण और बोतलबंदी के लिए सरकार द्वारा गोदाम को भुगतान की जाने वाली कीमत और अराक की खुदरा बिक्री के अधिकार के लिए पट्टेदारों द्वारा सरकार को बोतलबंद अराक की आपूर्ति के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत, आयुक्त द्वारा समय-समय पर सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित की जाएगी और इसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को दी जाएगी।

13. उपरोक्त अवलोकन से हम पाते हैं कि आबकारी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को शराब (इस मामले में अराक) के निर्माण आदि के लिए पट्टे का अधिकार प्रदान करती है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी, अर्थात् आबकारी आयुक्त, पट्टेदार को उसके पट्टे की शर्तों के अनुसार लाइसेंस प्रदान कर सकता है। उपरोक्त प्रावधान के पूरक के रूप में, 1987 के नियमों के नियम 3(1) में यह प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अराक के निर्माण या बोतलबंदी हेतु लाइसेंस प्रदान करेगा। 01.07.1993 से नियम 3 का उपनियम (2) लागू हो गया है, जिसके अनुसार 1987 के नियमों के नियम 3 के अंतर्गत लाइसेंस केवल राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी या एजेंसी या राज्य सरकार के विभाग को ही जारी किया जाएगा। इसी प्रकार मैसूर सेल्स को अराक के निर्माण और बोतलबंदी के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आबकारी ठेकेदारों का चयन किया जाता है, जिन्हें बाद में अपने-अपने क्षेत्र में खुदरा बिक्री के लिए अराक का लाइसेंस या परमिट जारी किया जाता है। उन्हें 1967 के नियमों के नियम

5(1) के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य का भुगतान करके गोदाम या डिपो से अराक प्राप्त करना आवश्यक है। नियम 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि खुदरा बिक्री में अराक केवल सीलबंद बोतलों या सीलबंद पॉलीथीन पाउच में ही बेचा जाएगा, जो गोदाम या डिपो से प्राप्त किए गए हों। इस प्रकार की खुदरा बिक्री के लिए, 1967 के नियमों के नियम 3 के अनुसार आबकारी ठेकेदार को दुकान में एक काउंटर का निर्माण करना आवश्यक है। शराब की खुदरा बिक्री का अधिकार निविदा, नीलामी या निविदा-सह-नीलामी आदि की संयुक्त प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है। 1987 के नियमों के नियम 17 के अनुसार, बोतलबंद शराब की आपूर्ति के लिए सरकार को शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत आयुक्त द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित की जाएगी। खुदरा मूल्य के संबंध में, 1967 के नियमों के नियम 4 में कहा गया है कि उत्पाद शुल्क ठेकेदार उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा मूल्य और अधिकतम सीमा मूल्य के दायरे में शराब बेच सकता है।

14. कर्नाटक राज्य में अराक के कारोबार के वैधानिक ढांचे का व्यापक सर्वेक्षण करने के बाद, आइए अब आयकर अधिनियम की धारा 206सी पर विचार करें। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त प्रावधान नीचे दिया गया है:

206-सी. मादक पेय, वन उत्पाद, स्क्रेप आदि के व्यापार से होने वाले लाभ और आय—

(1) प्रत्येक विक्रेता, क्रेता द्वारा देय राशि को क्रेता के खाते में डेबिट करते समय या उक्त क्रेता से नकद या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य माध्यम से ऐसी राशि प्राप्त करते समय, जो भी पहले हो, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी भी सामान के क्रेता से, उक्त तालिका के स्तंभ (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि आयकर के रूप में वसूल करेगा।

क्र.	वस्तु का प्रकार		वस्तु का प्रतिशत
(i)	(i) मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक मदिरा (भारत में निर्मित विदेशी मदिरा को छोड़कर) और तेंदू पत्ते		दस प्रतिशत

(ii)	वन पट्टे के तहत प्राप्त लम्बर		पंद्रह प्रतिशत
(iii)	वन पट्टे के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त लम्बर		पांच प्रतिशत
(iv)	लम्बर या तैदू पत्ते के अलावा कोई अन्य वन उत्पाद		पंद्रह प्रतिशत

बशर्ते कि यदि निर्धारण अधिकारी, क्रेता द्वारा किए गए आवेदन पर, निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाण पत्र देता है कि उसके सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सारणी में निर्दिष्ट वस्तुओं में से कोई भी वस्तु व्यापारिक प्रयोजनों के लिए नहीं बल्कि वस्तुओं या चीजों के निर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जानी है, तो प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने तक इस उपधारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(2) उपधारा (1) के तहत वसूली द्वारा कर वसूलने की शक्ति वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल नहीं होगी।

3) उपधारा (1) के अंतर्गत कोई भी राशि एकत्र करने वाला व्यक्ति सात दिनों के भीतर एकत्रित राशि को केंद्र सरकार के खाते में या बोर्ड के निर्देशानुसार जमा करेगा।

(4) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार एकत्रित की गई और उपधारा (3) के तहत भुगतान की गई कोई भी राशि उस व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान मानी जाएगी जिससे वह राशि एकत्रित की गई है और इस अधिनियम के तहत किए गए आकलन वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय का आकलन किया जाना है, उपधारा (5) के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे ऐसी एकत्रित राशि का क्रेडिट दिया जाएगा।

(5) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर वसूलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, राशि के डेबिट या प्राप्त की तिथि से दस दिनों के भीतर उस खरीदार को, जिसके खाते में ऐसी राशि डेबिट की गई है या जिससे ऐसा भुगतान प्राप्त हुआ है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि कर वसूल लिया गया है, और उसमें वसूल की गई राशि, कर की दर और ऐसे अन्य विवरण निर्दिष्ट किए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(5क) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर वसूलने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अर्धवार्षिक रिटर्न तैयार

करेगा और निर्धारित आयकर प्राधिकरण को ऐसे रिटर्न ऐसे प्रपत्र में, ऐसे तरीके से सत्यापित करके, ऐसे विवरणों के साथ और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(5ख) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, फ्लॉपी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी-रोम या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम (जिसे इसके बाद कंप्यूटर माध्यम कहा जाएगा) पर दाखिल किया गया रिटर्न उप-धारा (5क) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए रिटर्न माना जाएगा और मूल प्रति प्रस्तुत किए बिना, मूल प्रति की किसी भी सामग्री या उसमें वर्णित किसी भी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, उसके अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा।

(5सी) उपधारा (5 बी) के तहत दाखिल किए गए रिटर्न में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात्:-

(ए) कंप्यूटर मीडिया पर रिटर्न प्राप्त करते समय, कंप्यूटर मीडिया पर दाखिल किए गए दस्तावेजों को स्कैन करके आवश्यक जांच की जाएगी और मीडिया को निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा; और

(बी) निर्धारण अधिकारी डेटा की हानि के बिना कंप्यूटर मीडिया को डुप्लिकेट करके, स्थानांतरित करके, मास्टर करके या संग्रहीत करके सुरक्षित रखने का भी पूरा ध्यान रखेगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत संग्रह द्वारा कर वसूलने की शक्ति, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत कोई भी राशि वसूल करने वाला व्यक्ति, एकत्रित राशि को सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार के खाते में या बोर्ड के निर्देशानुसार जमा करेगा।

(6) कर वसूलने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर वसूलने में विफल रहता है, ऐसी विफलता के बावजूद, उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) उपधारा (6) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि विक्रेता कर वसूल नहीं करता है या कर वसूल करने के बाद इस धारा के अनुसार उसका भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे कर की राशि पर एक और एक चौथाई प्रतिशत प्रति माह या उसके भाग की दर

से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, उस तिथि से जिस तिथि से कर वास्तव में भुगतान किया गया था।

(8) जहां कर का भुगतान उपर्युक्त तरीके से नहीं किया गया है, तो उसके संग्रह के बाद कर की राशि और उस पर उपधारा (7) में निर्दिष्ट साधारण ब्याज की राशि विक्रेता की सभी परिसंपत्तियों पर प्रभार होगी।

(9) जहाँ निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हो कि क्रेता की कुल आय उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रासंगिक दर से कम दर पर कर वसूलने को उचित ठहराती है, वहाँ निर्धारण अधिकारी क्रेता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रासंगिक दर से कम दर पर कर वसूलने का प्रमाण पत्र देगा।

(10) जहाँ उपधारा (9) के तहत प्रमाण पत्र दिया जाता है, वहाँ कर वसूलने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र रद्द किए जाने तक, प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दरों पर कर वसूल करेगा।

(11) बोर्ड, करदाताओं की सुविधा और राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन मामलों और परिस्थितियों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बना सकता है जिनमें उपधारा (9) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया जा सकता है और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) “खरीददार” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नीलामी, निविदा या किसी अन्य माध्यम से उपधारा (1) में दी गई तालिका में निर्दिष्ट प्रकार की वस्तुओं की बिक्री में या ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के अधिकार में शामिल होता है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी,

(ii) ऐसी बिक्री के अनुसरण में प्राप्त ऐसी वस्तुओं की आगे की बिक्री में खरीददार,
या

(iii) ऐसा खरीददार जहां वस्तुएं उसे नीलामी के माध्यम से प्राप्त नहीं होती हैं और जहां खरीददार द्वारा बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किया गया है;

(ख) “विक्रेता” से तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या प्राधिकरण से है जो किसी केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो, या कोई कंपनी या फर्म या सहकारी समिति।

14.1. धारा 206सी की उपधारा (1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो विक्रेता है, तालिका में निर्दिष्ट वस्तुओं के खरीददार से तालिका की संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि वसूल करेगा। खरीददार द्वारा देय राशि को खरीददार के खाते से डेबिट करते समय या उक्त खरीददार से नकद, चेक या ड्राफ्ट आदि के माध्यम से ऐसी राशि प्राप्त होने पर कर संग्रह किया जाएगा। जहां तक मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों (भारत में निर्मित विदेशी शराब, अर्थात् आईएमएफएल को छोड़कर) का संबंध है, संग्रह की जाने वाली राशि 10 प्रतिशत है। उपधारा (3) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत ऐसी राशि एकत्र करने वाला कोई भी व्यक्ति संग्रह के 7 दिनों के भीतर उक्त राशि को केंद्र सरकार के खाते में या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देशानुसार जमा करेगा। उपधारा (4) स्पष्ट करती है कि धारा 206सी (1) के तहत एकत्र की गई और उपधारा (3) के तहत भुगतान की गई कोई भी राशि उस व्यक्ति की ओर से आयकर भुगतान मानी जाएगी जिससे राशि एकत्र की गई है और संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के समय ऐसी एकत्र और भुगतान की गई राशि के लिए उस व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाएगा। उपधारा (5) में कहा गया है कि ऐसा कर वसूलने वाला प्रत्येक व्यक्ति राशि के डेबिट या प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर क्रेता को प्रमाण पत्र जारी करेगा। उपधारा (5क) के अनुसार, कर वसूलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधियों के लिए अर्धवार्षिक रिटर्न तैयार करना होगा और उसे निर्धारित प्रपत्र में सक्षम आयकर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

14.2. उपधारा (6) प्रासंगिक है। उपधारा (6) कहती है कि कर वसूलने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति यदि कर वसूलने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता के बावजूद वह उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के खाते में वह कर जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा

जो उसे वसूलना चाहिए था। उपधारा (7) उस स्थिति से संबंधित है जहां कर वसूल नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में विक्रेता निर्धारित दर पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरी ओर, उपधारा (8) उस स्थिति से संबंधित है जहां विक्रेता कर वसूलने के बाद भी राशि जमा नहीं करता है। ऐसी स्थिति में भी वह ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

14.3. अब हम आयकर अधिनियम की धारा 206सी की व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या धारा 206सी के प्रयोजनों के लिए “खरीददार” और “विक्रेता” को परिभाषित करती है। व्याख्या (क) “खरीददार” को परिभाषित करती है, जबकि (ख) “विक्रेता” को परिभाषित करती है। स्पष्टीकरण (क) के अनुसार, “खरीददार” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नीलामी, निविदा या किसी अन्य माध्यम से उपधारा (1) में दी गई तालिका में निर्दिष्ट प्रकार की वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन “खरीददार” में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(ii) ऐसी बिक्री के अनुसरण में प्राप्त वस्तुओं की आगे की बिक्री में खरीददार;

(iii) वह खरीददार जहां वस्तुएं उसे नीलामी के माध्यम से प्राप्त नहीं होती हैं और जहां खरीददार द्वारा बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किया गया है।

14.4. दूसरी ओर, “विक्रेता” को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित प्राधिकरण या किसी कंपनी या फर्म या सहकारी समिति के रूप में परिभाषित किया गया है।

14.5. “खरीददार” की परिभाषा पर ध्यान देते हुए, स्पष्टीकरण (क) कहता है कि वह व्यक्ति जो नीलामी, निविदा या किसी अन्य माध्यम से किसी बिक्री में उपधारा (1) में दी गई तालिका में निर्दिष्ट प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है या ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, खरीददार कहलाता है। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर देखा है, “खरीददार” की परिभाषा में एक अपवाद खंड है। यदि खरीददार कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है या उसने आगे की बिक्री में वस्तुएं प्राप्त की हैं या यदि वस्तुएं उसे नीलामी के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई हैं और जहां खरीददार द्वारा बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति स्पष्टीकरण (क)

में दी गई परिभाषा के अनुसार “खरीददार” के दायरे में नहीं आएगा। चूंकि स्पष्टीकरण (क)(iii) पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए इसके महत्व को समझने के लिए हम इसे फिर से उद्धृत कर सकते हैं: एक खरीददार जहां वस्तुएं उसे नीलामी के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई हैं और जहां खरीददार द्वारा बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, व्याख्या (क)(iii) में व्याख्या (क) में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को “खरीददार” के अर्थ से बाहर रखने के लिए दो शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त यह है कि माल उसे नीलामी के माध्यम से प्राप्त न हो। दूसरी शर्त यह है कि खरीददार द्वारा बेचे जाने वाले माल का विक्रय मूल्य राज्य अधिनियम के तहत निर्धारित हो। इन दोनों शर्तों को ‘और’ शब्द से जोड़ा गया है। ‘और’ शब्द संयोजक है जिसका अर्थ है कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए; यह दोनों में से कोई एक नहीं है। इसलिए, व्याख्या (क)(iii) के अनुसार “खरीददार” की परिभाषा के दायरे से बाहर होने के लिए, दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

15. उपरोक्त के आलोक में, आइए एक उत्पाद शुल्क ठेकेदार की स्थिति का परीक्षण करें। ऊपर चर्चा की गई विचाराधीन योजना में, क्या ऐसे उत्पाद शुल्क ठेकेदार को आयकर अधिनियम की धारा 206सी की व्याख्या (क) के अर्थ में “खरीददार” माना जाएगा? उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों पर गौर करने पर पता चलता है कि मैसूर सेल्स निर्दिष्ट क्षेत्रों में अराक के निर्माण और बोटलबंदी के लिए लाइसेंसधारी है। नीलामी, निविदा या नीलामी-सह-निविदा आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पाद शुल्क ठेकेदारों का चयन किया जाता है, जिन्हें बाद में अपने-अपने क्षेत्रों में खुदरा अराक बेचने के लिए परमिट जारी किए जाते हैं। इन खुदरा विक्रेताओं, अर्थात् उत्पाद शुल्क ठेकेदारों को उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य का भुगतान करके मैसूर सेल्स द्वारा संचालित गोदाम या डिपो से अराक प्राप्त करना होता है। अराक सीलबंद बोटलों या सीलबंद पॉलीथीन पाउचों में प्राप्त की जाती है। यहाँ एक क्षण रुककर यह स्पष्ट होता है कि नीलामी आदि प्रक्रिया द्वारा आबकारी ठेकेदारों का चयन किया जाता है। इसके बाद उन्हें परमिट जारी किए जाते हैं। परमिट के आधार पर वे आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य का भुगतान करके गोदाम या डिपो से बोटलबंद (या सीलबंद पॉलीथीन पाउचों में) अराक प्राप्त करते हैं। फिर आबकारी ठेकेदार इस अराक को, चाहे वह सीलबंद बोटलों में हो या सीलबंद पॉलीथीन पाउचों में, अपने आवंटित क्षेत्र में खुदरा बेचते हैं। अतः, नीलामी आदि प्रक्रिया द्वारा आबकारी ठेकेदारों का चयन किया जाता है और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में अराक की खुदरा बिक्री का अधिकार दिया जाता है। यह नहीं कहा जा

सकता कि नीलामी के माध्यम से आबकारी ठेकेदारों द्वारा अराक की निश्चित मात्रा खरीदी जाती है। इस प्रकार, इस स्तर पर दो अलग-अलग लेन-देन होते हैं। पहला लेन-देन खुदरा बिक्री के अधिकार के लिए नीलामी आदि प्रक्रिया द्वारा उत्पाद शुल्क ठेकेदारों का चयन करना है। दूसरा लेन-देन, जो पहले लेन-देन पर निर्भर है, नीलामी के बाद सफल चयन हेतु जारी किए गए परमिटों के आधार पर उत्पाद शुल्क ठेकेदारों द्वारा खुदरा बिक्री के लिए अराक प्राप्त करना है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्पाद शुल्क ठेकेदारों द्वारा अराक नीलामी के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है। नीलामी के माध्यम से जो प्राप्त किया जाता है वह नीलामी के आधार पर सफल चयन हेतु जारी किए गए परमिटों के आधार पर अराक को खुदरा बेचने का अधिकार है। इस प्रकार, खंड (iii) के अंतर्गत पहली शर्त पूरी होती है।

15.1. ओम प्रकाश (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 206सी के तहत शराब व्यापार के संबंध में स्रोत पर कर संग्रह के मुद्दे पर विचार किया और इस बात पर भी विचार किया कि क्या सरकार द्वारा शराब व्यापार करने की अनुमति देने वाला लाइसेंसधारी, आयकर अधिनियम की धारा 206सी (11) के स्पष्टीकरण (क) में परिभाषित "खरीददार" होगा। इस न्यायालय ने माना कि "खरीददार" का अर्थ वह व्यक्ति होगा जिसे भुगतान के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, न कि वह व्यक्ति जिसे केवल उस व्यापार में व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है। सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों पर, जो लाइसेंसधारी को शराब व्यापार करने की अनुमति देते हैं, धारा 206सी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि लाइसेंसधारी उस धारा में संदर्भित "खरीददार" की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि खरीददार वस्तुओं का खरीददार होना चाहिए, न कि केवल वह व्यक्ति जिसे व्यवसाय करने का लाइसेंस प्राप्त होता है।

15.2. आबकारी ठेकेदार द्वारा उपरोक्त तरीके से अराक प्राप्त किए जाने के बाद, स्पष्टीकरण (क) (iii) के अंतर्गत दूसरी शर्त यह है कि उसे आवंटित क्षेत्र(क्षेत्रों) में 1967 के नियमों के नियम 4 के अनुसार निर्धारित विक्रय मूल्य पर अराक बेचना होगा। दूसरी शर्त का अर्थ यह है कि क्रेता द्वारा बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसी राज्य कानून द्वारा या उसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1967 के नियमों का नियम 4 आबकारी ठेकेदार को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम तल मूल्य और अधिकतम तल मूल्य की सीमा के भीतर अराक को खुदरा में बेचने में सक्षम बनाता है। एक न्यूनतम मूल्य और एक अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है जिसके भीतर आबकारी

ठेकेदार को अराक बेचना होता है। इस प्रकार, खुदरा में बेची जाने वाली अराक का मूल्य बाजार की शक्तियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एक पूर्व-निर्धारित सीमा के भीतर होता है। अतः, यद्यपि विधिक द्वारा मूल्य सीमा निर्धारित की गई है, यह नहीं कहा जा सकता कि न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित होने के कारण विक्रय मूल्य निश्चित नहीं है। विक्रय मूल्य विधिक द्वारा निर्धारित है, लेकिन एक निश्चित सीमा के भीतर, जिसके बाहर, चाहे वह अधिक हो या कम, आबकारी ठेकेदार द्वारा अराक को खुदरा में नहीं बेचा जा सकता। अतः, अराक को उस मूल्य पर बेचा जाता है जो 1967 के नियमों के नियम 4 के अंतर्गत विधिक रूप से निर्धारित है, और इस प्रकार दूसरी शर्त पूरी होती है।

16. चूंकि स्पष्टीकरण (क)(iii) के अंतर्गत अनिवार्य दोनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए आबकारी ठेकेदार या अराक बेचने वाले शराब विक्रेता आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के अंतर्गत परिभाषित "खरीददार" के दायरे में नहीं आएंगे।

17. हमने आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2001 को पारित आदेशों का अध्ययन किया है। उक्त आदेशों, विशेष रूप से निर्धारण वर्ष 2000-2001 के संबंध में पारित आदेश, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मुख्य आदेश है और जिसका अनुसरण अन्य निर्धारण कार्यवाहियों में किया गया है, के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह आदेश आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत पारित किया गया था। दिनांक 17.01.2001 के उक्त आदेश द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए निर्धारण अधिकारी ने घोषित किया कि मैसूर सेल्स आबकारी ठेकेदारों से 3,90,57,516.00 रुपये की राशि टीडीएस के रूप में एकत्र करने और जमा करने में विफल रही है, और इसलिए अपीलकर्ता को उक्त राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, धारा 206सी(6) के तहत ब्याज भी लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत उसी तारीख को मांग नोटिस जारी किया गया। उक्त आदेश पारित करने से पहले, यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 206सी और मैसूर सेल्स द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किया था।

18. हमने आयकर अधिनियम की धारा 206सी के विभिन्न उप-धाराओं का पहले ही विश्लेषण कर लिया है। उप-धारा (3) के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत टीडीएस एकत्र करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार के खाते में जमा करना होगा। उप-धारा (5ए) के तहत यह आवश्यक है कि धारा 206सी (1) के अनुसार टीडीएस एकत्र करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने

वाली अवधियों के लिए अर्धवार्षिक रिटर्न तैयार करे और उसके बाद उसे सक्षम निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। उप-नियम (6) में यह अनिवार्य है कि यदि कोई व्यक्ति जो टीडीएस (वसूली कटौती) एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है, उसे टीडीएस एकत्र करने में विफल रहने पर भी उक्त राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी होगी।

19. यद्यपि आयकर अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (6) या किसी अन्य प्रावधान में ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करने और उसके अंतर्गत आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट है कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी (6) के अंतर्गत पारित आदेश, जैसा कि वर्तमान मामले में है, संबंधित व्यक्ति के लिए प्रतिकूल है क्योंकि ऐसे आदेश के प्रतिकूल नागरिक परिणाम होते हैं। यह सर्वविदित कानून है कि जब किसी आदेश के प्रतिकूल नागरिक परिणाम होते हैं या वह संबंधित व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इस मामले में, यद्यपि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसका जवाब भी दाखिल किया गया था, फिर भी आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के तहत पारित ऐसे आदेश के परिणामों को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं होगा। भले ही कानून में नोटिस और सुनवाई के संबंध में कोई प्रावधान न हो, न्यायालय किसी भी पूर्वाग्रही आदेश को पारित करने से पहले नोटिस और सुनवाई की अंतर्निहित आवश्यकता को ध्यान में रखेगा। इसलिए, हम मानते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 206सी के तहत आदेश पारित करने से पहले, निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व है कि वह संबंधित व्यक्ति को नोटिस दे और उसे व्यक्तिगत सुनवाई सहित सुनवाई का पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान करे।

20. उपरोक्त चर्चाओं और निकाले गए निष्कर्षों के मद्देनजर, हमारे लिए इस मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, उपरोक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है, क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 206सी मैसूर बिक्री के संबंध में लागू नहीं होती है और जिन शराब विक्रेताओं (ठेकेदारों) ने अपीलकर्ता से नीलामी में बिक्री अधिकार खरीदे हैं, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 206सी के स्पष्टीकरण (क) के अर्थ में "खरीदार" नहीं कहा जा सकता है। हम यह भी मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं और परिणामस्वरूप, दिनांक 17.01.2001 के आदेशों को चुनौती देने वाली रिट अपील को खारिज करना उचित नहीं था।

21. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि अपील स्वीकार की जानी चाहिए। तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु की खंडपीठ द्वारा रिट अपील संख्या 7926/2003 और संबंधित रिट अपीलों में दिनांक 13.03.2006 को पारित निर्णय और आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है;

(ii) कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 6869-6874/2001 और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में दिनांक 27.10.2003 को पारित निर्णय एवं आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है; और

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 206सी(6) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997 और 1995-1996 के लिए दिनांक 17.01.2001 को बेंगलुरु के आयकर उप आयुक्त (टीडीएस)-1 द्वारा पारित आदेश, साथ ही

मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य

और आयकर अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत दिनांक से जारी परिणामी मांग नोटिसों को एतद्वारा निरस्त और रद्द किया जाता है।

22. तदनुसार दीवानी अपील स्वीकार की जाती है। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

† शीर्ष टिप्पणियाँ अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गई हैं।

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।